

सं० ओ०वि०/अम्बाला/33-86/17003.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० प्रेजीडेंट/मैनेजर, को०-ओपरेटिव सोसायटी बिल्लास, तहसील कालका (अम्बाला) के श्रमिक श्री अब्दुल करीम तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-अम, दिनांक 15 अप्रैल, 1985, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री अब्दुल करीम एलिआस गोकुल, सुपुत्र श्री रमजान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/262-85/17009.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रशासक स्टेट ऑफिसर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेंक्टर-6, फरीदाबाद, (2) कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण डिविजन नं. II, फरीदाबाद के श्रमिक श्री रणवीर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-अम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-अम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री रणवीर, पुत्र श्री सिवली की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/अम्बाला/15-86/17016.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) दी. आफिसर, इन्चार्ज, सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च सेंटर, सेंक्टर 27, चण्डीगढ़, (2) दी सीनियर टेक्नीकल असिस्टेंट, सेंट्रल सोयल एण्ड वाटर कन्जरवेशन, रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट रिसर्च, फार्म मनसा देवी, डाकखाना मनी माजरा, पंचकुला (अम्बाला) के श्रमिक श्री जसवन्त सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44) 84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जसवन्त सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?